B-3

L-21

Economy

3. RRR = Reverse Repo Rate (रिवर्स रेपो दर)

⇓

ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को सोखता (Absorb) है।

इस दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास अपने धन को जमा करा सकते हैं। इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक को सौंपी जाने वाली G-Sec की पुनर्खरीद का वादा करना पड़ता है।

RRR में बढ़ोत्तरी से अर्थव्यवस्था में तरलता का स्तर कम हो जाता है क्योंकि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास अधिक मात्रा में धन जमा कराने का प्रयास करते हैं।

उपर्युक्त के विपरीत यदि RRR कम होती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता का स्तर अधिक हो जायेगा क्योंकि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास कम मात्रा में धन रखना चाहेंगे।

यह देखा गया है कि कई बार यूरोपियन राष्ट्रों में इस प्रकार की ब्याज दर न केवल 0 (शून्य) बल्कि नकारात्मक कर दी जाती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

4- SDF Rate (Standing Deposit facility)

(i) अप्रैल 2022 में शुरू।

(ii) उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर।

(iii) इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक Overnight के लिए रिजर्व बैंक के पास धन जमा करवा सकते हैं।

(iv) रिजर्व बैंक द्वारा G-Sec देने की आवश्यकता नहीं होती

(v) RBI के इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, e-Kuber के माध्यम से बैंक इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

(vi) रिजर्व बैंक द्वारा यह कहा गया है कि वह SDF Rate को रेपो रेट की तुलना में 25 आधार बिन्दु (0.25%) नीचे रखेगा

Note - इसे UDF (Uncollateralised Deposit facility) भी कहते हैं।

वर्तमान में इसका स्तर 6.25% है। इस दर के लागू होने के बाद RRR का महत्व कम हो गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि RRR का स्तर काफी लम्बे समय से 3.35% पर बना हुआ है।

KGS IAS

5⇒ MSF दर (Marginal Standing facility)

1- मई २०११ में शुरू।

२- वाणिज्यिक बैंक overnight के लिए धन उधार ले सकते हैं (RBI से)

3- वर्तमान नीति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक इस दर को रेपो दर की तुलना में २५ आधार बिन्दु (0.25%) ऊपर बनाये रखता है।

4- वर्तमान में इसका स्तर 6.75% है।

Note- वाणिज्यिक बैंक NDTL के २% तक MSF दर के आधार पर रिजर्व बैंक से overnight के लिए धन उधार ले सकते हैं। कोविड के समय यह अनुपात 3% कर दिया गया था।

6⇒ BPLR (Benchmark Prime Lending Rate)

1- शुरू - 2003

2- बैंकों द्वारा अपने Good-borrowers से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर।

7- Base Rate

1- शुरू - 2010

२- दीपक मोहन्ती समिति की सिफारिशों पर

3- लक्ष्य - बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित करना।

4- इसके अन्तर्गत बैंकों से कहा गया कि वह एक निश्चित दर से नीचे अपनी BPLR नहीं ले जा सकते हैं।

Note- अन्य बातों के अलावा, Base rate के निर्धारण में कोषों की औसत लागत (Average Cost of funds) को मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है।

B. MCLR (Marginal Cost of funds-based Lending Rate)

- शुरुआत – 2016 (PT-2016)
- इसके अन्तर्गत BPLR के निर्धारण में Average Cost के बजाय Marginal Cost of funds (कोषों की सीमांत लागत) को ध्यान में रखा जाता है।

रेपो दर में परिवर्तन के बाद बैंकों द्वारा ली जाने वाली नयी जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को Marginal Cost of funds माना जाता है।

9- EBLR (External Benchmark-based Lending Rate)

- शुरुआत : 2019
- इसके अन्तर्गत, वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किसी एक ग्राह्य कारक को EBLR के निर्धारण में प्रयुक्त कर सकते हैं।

(i) रेपो रेट
(ii) यील्ड रेट (Yield Rate) ⟶ प्रतिफल की दर
↓
91-days Treasury Bills
(iii) यील्ड रेट (Yield Rate) ⟶ 182-days Treasury Bills

Note - उपर्युक्त व्यवस्था Auto, Housing, MSMEs, Personal आदि क्षेत्रों से जुड़े FRLs (Floating Rate Loans) के लिए लागू की गई है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR